आईडीबीआई और आईआईएफसीएल के बीच बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए सहमति ज्ञापन

मुंबई, 10 अप्रैल 2007: इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लि. (आईडीबीआई) और **इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल)** ने बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं के संयुक्त रूप से वित्तपोषण के लिए अपने संसाधनों के निवेश हेतु सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये.

इस सहमति ज्ञापन पर आईडीबीआई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री वी.पी. शेट्टी और आईआईएफसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस.एस. कोहली ने हस्ताक्षर किये.

सहमति ज्ञापन के अनुसार आईडीबीआई-आईआईएफसीएल मिलकर ऐसे उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान करेंगे जो किसी किसी बुनियादी परियोजनाओं को विकसित या परिचालन व रखरखाव या विकसित व परिचालन व रखरखाव करेंगे. वित्तीय मध्यस्थ अन्य क्षेत्रों के अलावा सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, जल आपूर्ति, पॉवर, औद्योगिक पार्कों सरीखे बुनियादी परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करेंगे.

इस अवसर पर, श्री शेट्टी ने कहा कि ''चूंकि इस क्षेत्र के प्रचुर अनुभव व प्रतिभाओं से संपन्न दो बड़े वित्तीय मध्यस्थ अपनी संयुक्त शक्ति लगाएंगे अत: बुनियादी परियोजनाओं को ऋण देने की दिशा में और अधिक तेजी आएगी. यह एमओयू एक सही अवसर पर उठाया गया कदम है क्योंकि सरकार का अनुमान है कि देश में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 320 बिलियिन डॉलर से भी अधिक की जरूरत होगी. इस समझौते से दोनों ही संस्थाएं लाभान्वित होंगी और देश की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार के रूप में विकास बैंकिंग के प्रति हमारी निष्ठापूर्ण प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि हुई है.''

श्री कोहली के अनुसार '' आईआईएफसीएल -आईडीबीआई की संयुक्त ताकत से देश में बुनियादी परियोजनाओं को ऋण देने की गति को और अधिक बढावा मिलेगा. आईडीबीआई ऋण मूल्यांकन, संसाधन संग्रहण और सिंडिकेशन के क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करेगा जबकि आईआईएफसीएल अपनी दीर्घकालिक निधीयन सहायता का सहयोग प्रदान करेगा जिससे आईडीबीआई की देयताओं में अपेक्षाकृत अल्पकालिक प्रकृति की आस्ति - देयता असंगति, यदि कुछ हुई, का समाधान हो सकेगा.''

बुनियादी परियोजनाओं की पहचान, चाहे वे सार्वजनिक/निजी/संयुक्त क्षेत्र की हों, आईडीबीआई और आईआईएफसीएल की पारस्परिक विचार विमर्श के जरिए की जाएगी. एमओयू में यह व्यवस्था है कि आईडीबीआई और आईआईएफसीएल बुनियादी परियोजनाओं को मदद देने के लिए, जिनमें निधि के वापिस आने में लंबी अवधि लग जाती है, स्पर्धात्मक शर्तों पर निधियों के अपने संसाधन मिलकर लगाएंगे.

आईडीबीआई के बारे में

आईडीबीआई अब एक यूनिवर्सल बैंक है. यह अपने ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाएं तथा ग्राहकीकृत वित्तीय समाधान तैयार करने एवं उपलब्ध कराने के लिए नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है. 31 दिसम्बर 2006 को बैंक के तुलन पत्र का आकार 97,754 करोड़ रुपये था. बैंक देश भर में तेजी से शाखा विस्तार कर रहा है. आईडीबीआई की आजकल 432 शाखाएं, 18 विस्तार काउंटर व 521 एटीएम हैं जो 255 शहरों में फैले हुए हैं.

आईडीबीआई को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगातार पुरस्कार मिलते रहे हैं. हाल में अपने ग्राहक-केन्द्रित आईटी पहल कार्यों की मान्यता के रूप में प्रतिष्ठित संस्थान - इंस्टिट्यूट फॉर डेवलपमेन्ट एण्ड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नॉलॉजी (आईडीआरबीटी) से वर्ष 2005-06 के लिए आईडीबीआई को दो विशेष पुरस्कार 'बेस्ट इंटरनेट बैंक फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर्स' तथा 'आईटी टीम ऑफ दि ईयर' प्राप्त हुए.

वित्तीय वर्ष 2007 के पहले नौ महीनों के दौरान आईडीबीआई के निवल लाभ में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 16% की वृद्धि हुई और यह 417 करोड़ रुपये रहा. 31 मार्च 2006 को समाप्त पूर्ण वित्तीय वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के नई पीढ़ी के इस बैंक ने 561 करोड़ रुपये का निवल लाभ अर्जित किया था.

<u>आईआईएफसीएल के बारे में</u>

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित सरकार के पूर्ण स्वामित्व की कंपनी है. यह देश में विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए शीर्ष भूमिका निभाने के लिए स्थापित की गई है. यह कंपनी पात्र परियोजनाओं को प्रत्यक्ष ऋण देने, बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को 10 वर्षों व अधिक के ऋणों के लिए पुनर्वित्त, और सरकार द्वारा यथास्वीकृत प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान करती है. कंपनी का ध्यान निम्न क्षेत्रों - सड़क व पुलों, रेल्वे, बंदरगााहों, हवाई अड्डों व अन्य परिवहन परियोजनाओं; पॉवर, गैस पाईपलाईन, पर्यटन संबंधित बुनियादी सुविधाओं, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्रों, एसईजेड में बुनियादी सुविधाओं की परियाजनाओं के लिए वित्तपोषण पर केंद्रित है.